सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन

7580. **श्री रामजी लाल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलावटी मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है!

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा को इस वर्ष और अगले वर्ष में कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जायेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जबकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुपीरियर मिट्टी के तेल सहित छः आवश्यक वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है, वहीं उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वास्तविक वितरण की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल कार्य में, जिसमें चार लाख से अधिक उचित दर दुकानें शामिल हैं, यह-तत्र कुछ कमियों से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल को अन्यत्र बेचे जाने से रोकने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने इस उत्पाद को नीले रंग से रंगना शुरू किया है। जहां कहीं भी राज्य सरकारों ने सहमति दी है वहां थोक विक्रेताओं को मिट्टी के तेल की दरवाजे तक सुपुर्दगी की योजना भी शुरू की गई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष रूप से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में, उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि आवश्यक वस्तुओं का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देख-रेख में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(ग) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपीरियर मिट्टी के तेल का थोक में मासिक आवंटन करती है। 1994 के दौरान हरियाणा को किया गया औसत मासिक आवंटन 12823 मी. टन था। हरियाणा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल का वर्तमान मासिक आवंटन 13040 मी. टन (जून, 1995 के लिए आवंटन) है।

Steps to ensure passing of excise duty concessions to consumers

7581. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what concrete/specific measures Government have taken so far to ensure that the excise duty benefits in reality are passed on to the consumers;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) what action Government have taken against the industries that have defaulted in the matter of excise duty concession during the year 1994-95;

(d) if no action has been taken the reasons therefor;

(e) whether Government propose to formulate any new scheme to give some relief to consumers who are finding it difficult to meet their day to day expenses on account of steep rise in prices of essential commodities; and

(f) whether Government have any check on the shopkeepers who are charging high rates of goods from the customers after sticking desired stickers of price indication: if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) For protecting the interest of consumers in respect of prepacked commodities, the following steps have been taken by this Ministry:

(i) An advertisement has been issued in the National Newspapers inviting the attention of the manufacturers of prepacked commodities to pass on the benefit of recent tax cuts to consumers and warning the dealers/traders of penal action if the provisions are not compiled with.

(ii) Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has written letters to all Chief Ministers of the States and UTs urging them to take necessary steps under the rules to ensure that the consumers are not charged more than the revised price announced by the Manufacturers.

(iii) Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has also written letters to the Presidents of all the four apex industry Association requesting them to ensure that their members pass on the benefits of duty concessions to the consumers.

(iv) Letter has been written to all Secretaries in charge of the Weights and Measures Department in the States and Union Territories for ensuring strict implementation of the provisions of the Standards of Weights and Measures (Packed Commodities) Rules, 1977.

(v) Letters have been written to the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) with a request to conduct a study on whether the industries have passed on the benefits of tax concessions to the consumers in respect of some selected items on sample basis.

(c) and (d) Name, Sir. The Ministry of Finance have informed that there is no provision under the Central Excise laws to take action against the industries that have defaulted in the matter of passing on of duty concessions.

(e) Government monitors the prices of major essential commodities to see that prices of these commodities do not rise sharply. Some essential commodities are also supplied through Public Distribution System on prices below the market prices to the poor and vulnerable sections of the society.

(f) Under the provisions of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 after the commodities are packed, the declaration of sale price and other declarations can not be altered. The maximum price declared on the package is the upper limit of the price which a retailer can charge from the consumer. He can, however, charge price lower than the price marked on the package.

खाद्य तेलों की मांग और उनका उत्पादन

7582. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 8 मई, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5042 के दिये गये उत्तर को देखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में खाद्य तेलों की मांग